दैनिक
स्वर्णिम प्रदेश
PRN: MCN/329/2025-2027
epaper.swarnimpradesh.in
संरक्षक: मां वैष्णो देवी

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें
अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो दैनिक स्वर्णिम प्रदेश आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनी नोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।
ईमेल: swarnimpradesh@yahoo.com
या वाट्सऐप नं. 8898271111

वर्ष : 8 • अंक : 274 • मुंबई, शुक्रवार 17 अप्रैल, 2026 • पृष्ठ : 6 • मूल्य: 2 रुपये • संपादक : सुनील कुमार तिवारी • Email: swarnimpradesh@yahoo.com
www.swarnimpradesh.in

महिला आरक्षण पर बोले पीएम मोदी: 'यह महिलाओं का हक है'

संवाददाता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में सभी दलों से सरकार की ओर से लाए गए तीन विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कराने का अनुरोध किया ताकि इससे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि दशकों से महिला आरक्षण को रोका जाता रहा है।

अब इसका प्रायश्चित करने का समय है। वे मानते हैं कि देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान है और इस ऋण को हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में परिसीमन और उसके बाद महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े तीन विधायकों पर एक साथ जारी चर्चा में भाग लिया। चर्चा कल तक चलेगी और अंत में गृह मंत्री इसका जवाब देंगे। विधेयकों में एक संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे पारित कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। चर्चा में भाग लेते हुए एक तरफ प्रधानमंत्री ने विधेयकों को राजनीतिक बताने के विपक्ष के आरोपों का खंडन किया तो दूसरी ओर स्पष्टीकरण भी दिया कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होगा। साथ ही लोकसभा की सीटों में इजाफा समय की मांग है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से विधायिका का सामर्थ्य बढ़ेगा। इसे राजनीति के तराजू से नहीं तोलना चाहिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। उन्होंने कहा, "हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं... जी नहीं! उसका हक है। हमने कई दशकों से रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित कर उस पाप से मुक्ति पाने का अवसर है।" मोदी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार की नीयत साफ है और हमें शब्दों से खेलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हो... ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकार रही, जिनके काल में जो परिसीमन हुआ, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा चाहिए तो वादा देता हूं... क्योंकि अगर नीयत साफ है, तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है।" विपक्ष के सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति करने के आरोपों का प्रधानमंत्री ने खंडन किया।

गोरेगांव में डेकोरेशन यूनिट में भीषण आग, दमकल ने पाया काबू, ट्रैफिक प्रभावित

संवाददाता

मुंबई। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके में गुरुवार सुबह एक सजावट सामग्री बनाने वाली यूनिट में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना बांगुर नगर मेट्रो स्टेशन के पास लिंक रोड स्थित मोतीलाल नगर नंबर 2 में हुई। जानकारी के अनुसार, आग सुबह करीब 9:30 बजे निधि डेकोरेटर नामक यूनिट में लगी, जो डी-मार्ट के सामने स्थित है।

आग लगते ही मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) मौके पर पहुंची और इसे प्रारंभ में 'लेवल-I' श्रेणी की आग घोषित किया गया। दमकल विभाग की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि, आग लगने के कारण लिंक रोड पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ और बांगुर नगर सिग्नल के पास लंबा जाम लग गया, क्योंकि दमकल की गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत से घने धुएं के गुबार

दूर तक दिखाई दे रहे थे, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, पास स्थित बांगुर नगर मेट्रो स्टेशन की सेवाएं सामान्य रहीं और मेट्रो संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग द्वारा आग पूरी तरह बुझने और क्षेत्र ठंडा होने के बाद विस्तृत जांच की जाएगी।

इंडी गठबंधन की बैठक में महिला आरक्षण पर समर्थन, परिसीमन का विरोध

संवाददाता

नई दिल्ली। संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। विपक्षी दलों के सदन के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे के कार्यालय में मुलाकात कर रणनीति बनाई।

इस विशेष बैठक में तीन अहम विधेयक, जिनमें 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने और चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से जुड़े बिल शामिल हैं पर चर्चा की गई। विपक्ष ने सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने और परिसीमन के प्रावधानों पर चिंता जताई है। बैठक में राहुल गांधी, जयराम रमेश, सैयद नसीर हुसैन, प्रमोद तिवारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) से सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस से सागरिका घोष समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा कि विपक्ष संसद को महिला आरक्षण के नाम पर लाए गए दोषपूर्ण परिसीमन विधेयकों से हाईजैक नहीं होने देगा। विपक्षी दल एकजुट हैं और लोकतंत्र पर इस हमले का डटकर मुकाबला करेंगे। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक का पूरा समर्थन करता है, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन असंतुलन पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को लगभग 135 सीटें मिलेंगी, जबकि केरल को केवल 22.5 सीटें। इस असमानता के कारण विपक्ष सरकार के दृष्टिकोण का विरोध करता है।

महिला आरक्षण तुरंत लागू हो, परिसीमन फिलहाल रोका जाए: उद्धव ठाकरे

संवाददाता

मुंबई। शिवसेना(यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल लागू करने की जोरदार मांग करते हुए कहा है कि इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़कर देरी करना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद द्वारा 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बिना किसी विलंब के लागू किया जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का मुद्दा बेहद संवेदनशील और व्यापक राष्ट्रीय प्रभाव वाला है, इसलिए इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने जोर दिया कि इस प्रक्रिया के लिए गहन अध्ययन, व्यापक विचार-विमर्श और राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति आवश्यक है, ताकि लोकतांत्रिक ढांचे की निष्पक्षता बनी रहे। इस मुद्दे को लेकर नई दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन भाजपा द्वारा इसकी प्रक्रिया को संभालने के तरीके पर आपत्ति है। चर्चा के दौरान प्रस्तावित परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के मुद्दे पर भी चिंता जताई गई, जिससे राज्यों के प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव संभव है। नेताओं ने आशंका जताई कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के कारण इसके लागू होने में अनावश्यक देरी हो सकती है। बैठक में सुप्रिया सुले और संजय राउत सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जबकि उद्धव ठाकरे ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि महिला सशक्तिकरण को प्रक्रियात्मक जटिलताओं की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाना चाहिए। ठाकरे ने अपने बयान में दोहराया कि महिला आरक्षण विधेयक को पहले ही संसदीय मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए, जबकि परिसीमन को तब तक टाल देना चाहिए जब तक इस पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति न बन जाए। उन्होंने इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताया। इस बीच, संसद का विशेष सत्र भी शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य महिला आरक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। प्रस्तावित कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, हालांकि इसका क्रियान्वयन परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव होगा।

आंध्र प्रदेश के कर्नुल में सड़क हादसा, कर्नाटक के 8 श्रद्धालुओं की मौत

संवाददाता

हैदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश के कर्नुल जिले में गुरुवार तड़के एक सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 12 अन्य घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 167 पर कर्नुल जिले के धर्मापुर टोल प्लाजा से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर कर्नाटक-आंध्र प्रदेश सीमा के पास हुआ। पुलिस के अनुसार प्रसिद्ध तीर्थस्थल मंत्रालयम स्थित श्री राघवेंद्र स्वामी मठ में दर्शन के लिए श्रद्धालु एक छोटी पिकअप गाड़ी से जा रहे थे। तभी कर्नाटक-आंध्र प्रदेश सीमा पर तड़के 3.30 बजे मंत्रालयम के चिलकलाडोना के पास पिकअप गाड़ी और रेडी-मिक्स लॉरी की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। हादसे के समय पिकअप वाहन में कुल 21 लोग सवार थे। इनमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों को यममिगनूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान कुमार (60), दीपिका वीणा (35), सुनील (40), बेल्ली (3), मीनाक्षी (60), पुट्टम्मा (60), तयम्मा (60) और लोलेक्षी

के रूप में हुई है। यममिगनूर उप-मंडल की डीएसपी भार्गवी ने बताया कि सात घायलों को बेहतर उपचार के लिए बाद में कुर्नुल स्थानांतरित किया गया, जबकि चार अन्य का एरिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की हालत स्थिर बताई गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही अधिक जानकारी सामने आएगी। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि दो वाहनों की टक्कर में आठ लोगों की जान चली गई। परिवहन मंत्री मंडिपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने भी इस भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि श्रद्धालु धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे और इस दौरान यह हादसा हो गया।

ठाणे में अवैध पेट्रोलियम परिवहन का पर्दाफाश, 20 हजार लीटर डीजल जैसा पदार्थ और टैंकर जब्त

संवाददाता

मुंबई। रेशनिंग विभाग को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर ठाणे के कोपरी पुलिस थाना क्षेत्र में तड़के शिधावाटप उड़न दस्ते और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 20 हजार लीटर डीजल जैसे अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के साथ एक टैंकर जब्त किया गया। इस कार्रवाई में करीब 53 लाख रुपये का माल बरामद किया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है, ऐसी जानकारी नियंत्रक शिधावाटप विभाग ने दी है। 16 अप्रैल 2026 को तड़के करीब 1 से 1.30 बजे के बीच एमएच-46-सीयू-7536 नंबर का टैंकर बिना किसी वैध दस्तावेज के बड़े पैमाने पर डीजल जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन कर रहा था, ऐसी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। इसके

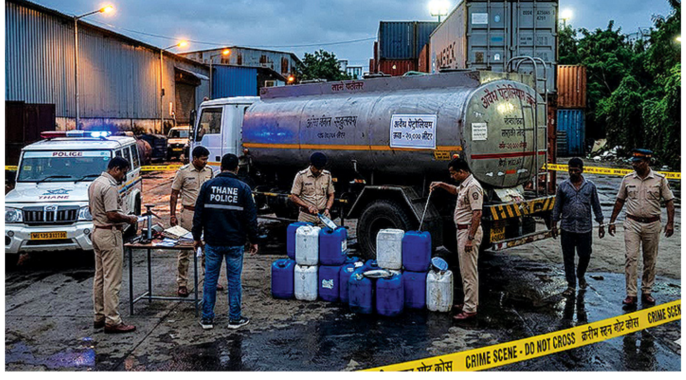

आधार पर उपनियंत्रक शिधावाटप 'फ' परिमंडल ठाणे के मार्गदर्शन में और कोपरी पुलिस स्टेशन के सहयोग से जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संबंधित टैंकर को रोका गया, जिसमें करीब 20 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार पाया गया। इस संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर यह माल अवैध पाया गया। तत्काळ कार्रवाई करते हुए टैंकर सहित पूरा माल जब्त कर लिया गया। इस प्रकरण में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उपनियंत्रक शिधावाटप कार्यालय 'फ' परिमंडल ठाणे तथा कोपरी पुलिस स्टेशन की संयुक्त कार्रवाई के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसआरए सीईओ ने करोड़ों खर्च कर कार्यालय संवारा, पर तोड़क दस्ते का अभाव

■ अतिक्रमण हटाने के लिए बीएमसी पर निर्भर एसआरए

संवाददाता

मुंबई। झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण (एसआरए) में सीईओ के पद पर डॉ. महेंद्र कल्याणकर के आने के बाद से एसआरए कार्यालय को चमकाने पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। हालांकि, एसआरए एक प्लानिंग अथॉरिटी होने के बावजूद अतिक्रमण निष्कासन के लिए इसके पास स्वयं का तोड़क दस्ता और आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नहीं है। इस कारण एसआरए के अधिकारी आज भी कार्रवाई के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) पर निर्भर हैं। बीएमसी से तोड़क दस्ता और संसाधन न मिलने के कारण कई बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अटक जाती है।

ताजा मामला बीएमसी के एच/पूर्व विभाग से जुड़ा है, जहां एसआरए के सक्षम प्राधिकारी डॉ. मोहन नलदकर ने सांताक्रूज पूर्व, वकोला स्थित डिसूजा एंड मिरांडा चाल सहकारी गृहनिर्माण संस्था में डेवलपर मे.अजीब इन्वेस्टमेंट द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बीएमसी एच/पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त को दिनांक 25 फरवरी 2026 को पत्र लिखकर 17 मार्च 2026 के लिए तोड़क दस्ता और कामगारों की मांग की, लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद 30 मार्च 2026 को पुनः पत्र लिखकर 16 अप्रैल 2026 के लिए तोड़क दस्ता और कामगारों की मांग की गई, जिसपर काफी मशक्कत के बाद सहायक आयुक्त मृदुला अंडे ने स्टॉप व तोड़क दस्ता उपलब्ध कराए। जिसके बाद बिल्डर के अतिक्रमण पर एसआरए की टीम ने कार्रवाई की। मतलब एक अतिक्रमण को हटाने के लिए एसआरए को एक महीने से अधिक का समय लगा। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसआरए की कार्यप्रणाली कितनी तेजी से गतिशील है। इस स्थिति से यह सवाल उठता है कि झोपड़पट्टी के विकास और 'झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई' का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। एसआरए के सीईओ महेंद्र कल्याणकर द्वारा किए जा रहे बड़े-बड़े दावों की हकीकत अब सामने आती दिख रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षों से लंबित एसआरए परियोजनाओं में झोपड़ियों की जगह अब अवैध इमारतें खड़ी हो गई हैं। इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि योजना प्राधिकरण एसआरए है, जबकि एसआरए के पास खुद का तोड़क दस्ता नहीं है। ऐसे में अवैध निर्माणों को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण मिलना स्वाभाविक माना जा रहा है।

संपादकीय

भारत में अनगिनत एपस्टीन फाइल?

आज दुनिया में एपस्टीन फाइल की चर्चा है, जहाँ तमाम छोटी-छोटी लड़कियों को इंजेक्शन लगाकर उनके साथ बलात्कार किए गए। उनका रक्त हमेशा जवान रहने के लिए पीया गया। इतने से मन नहीं भरा, तो उन्हें मारकर खाया गया, जिसमें विश्व भर के बड़े अय्याश नेताओं और पूंजीपतियों के नाम शामिल हैं। समूची एपस्टीन फाइल ही सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि नेता और धनपशु के वेष में सार्वजनिक रूप से घूम रहे दरिंदों के चेहरे से कृत्रिम नकाब उतर कर असली चेहरा सामने आए। भारत में हर दिन सैकड़ों मासूम बच्चे-बच्चियां और महिलाएं गायब हो रही हैं। शासन-प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही; जिम्मेदार लोग अंधे, बहरे और गूंगे बन गए हैं। आखिर इतने लोग गायब कैसे होते हैं? क्या कोई ऐसा गैंग है जिसका काम ही है कैसे भी हो गायब करना? कहीं अंग प्रत्यारोपण के लिए तो गायब नहीं किया जा रहा? दिल्ली में एक डॉक्टर के बंगले में भी यही होने के समाचार आते रहे थे। बताया गया कि बंगले के पास बह रहे नाले में तमाम मानव कंकाल मिले थे, जिस घटना ने देश को हिला दिया था; लेकिन कोर्ट ने सबूत नहीं होने के कारण नौकर को बेदाग बरी कर दिया था, फिर भी सवाल बाकी रह गए। उस नाले में बरामद कंकाल किसके थे? जांच करने वाली एजेंसी और फॉरेंसिक लैब ने सच पर से पर्दा क्यों नहीं उठाया? नाशिक में अशोक खरात नामक कथित तांत्रिक, जिसे नेवी का पूर्व अधिकारी बताया गया और जिसके संबंध सत्ता के बड़े-बड़े नेताओं के साथ रहे—सोशल मीडिया में खरात के साथ बड़े-बड़े नेताओं और मंत्रियों की फोटो संबंधों का खुलासा करती रही। संभ्रांत घरों की शिक्षित महिलाएं, यहाँ तक कि महिला आयोग की चेयरमैन की फोटो भी उस ढोंगी तांत्रिक के साथ वायरल हुई। यह भी बताया जाता रहा कि अमावस्या की रात बड़े-बड़े राजनेता उक्त तांत्रिक के बंगले में आते रहे हैं—यह समझने की बात है, कहने की नहीं। उक्त ढोंगी धूर्त बाबा ने सारी महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो भी चुपके से बनाकर ब्लैकमेल किया, इसी कारण उसने कई सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। उसके पास से तमाम वीडियो पुलिस ने जब्त किए, लेकिन उसके संबंध में कौन सी कार्रवाई की जा रही है, यह कहीं चर्चा में नहीं है।

अभी नाशिक का सेक्स स्कैंडल का खुलासा भी नहीं हुआ कि अब महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 19 वर्षीय मुख्य आरोपी मोहम्मद अयान (उर्फ तनवीर) को 180 से अधिक नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और 350 से अधिक अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के चार मुस्लिमों द्वारा सोशल मीडिया में वायरल किए जाने की बात अत्यंत गंभीर है। सोचिए, यदि गेरुआधारी बाबा के स्कूल में छात्राओं के साथ खुद बाबा बलात्कार करता हो, तो शिक्षा का क्या होगा? गेरूए या भगवा रंग का क्या होगा? यहाँ तक कि बहुचर्चित एक बाबा के आश्रम से कई महिलाओं को वैन में बैठाकर बेचने जा रहे लोगों को पकड़ा गया। देश में स्कूल और आश्रम कहीं भी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। एक तरफ सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं आज महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, जबकि बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं। इतिहास के छात्र जानते होंगे कि सम्राट हर्षवर्धन के शासन में आया चीनी यात्री लिखता है कि कश्मीर से अकेली महिला टोकरी में स्वर्ण आभूषण लेकर कन्याकुमारी तक चली जाए, तो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। उसी भारत में आज नित्य ही हजारों महिलाएं और लड़कियां गायब हो रही हैं। पुलिस सत्ता की सेवा के साथ भ्रष्टाचार में डूबी रहती है और अपराधियों को सलाम ठोकती है, जबकि गरीबों को बेगुनाह होने के बावजूद जेल भिजवाती है। कौन कहेगा कि भारत में कानून का राज्य स्थापित हुआ है? सत्ता को चाटुकार पसंद हैं और सच बोलने वालों को जेल भेजा जाता है। जब सत्ता के दर्प में खुद विधायक ही बलात्कार करते हों और न्यायालय आरोपियों को निर्दोष मानकर रिहा करती हो, तो निश्चित ही इसके पीछे जांच एजेंसियों का भ्रष्टाचार ही कारण है, जो ठोस सबूत देने में असफल रहती हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैंः बलात्कारी के सत्ता के साथ रिश्ते हों या फिर जांच करने वाली पुलिस की जेब गर्म की गई हो। अब तो भारत में बलात्कार जैसे एक फैशन बन गया है, जिसमें राजनेता और पुलिस अधिकारी सहित तमाम युवक शामिल हैं। अभी तक जितने मामले सामने आए हैं, उनमें बहुसंख्य हिंदू लड़कियों का ही बलात्कार होता है। लव जिहाद की बात हो या कोई अन्य प्रेम प्रकरण, सबमें हिंदू लड़कियां ही टारगेट क्यों होती हैं? निश्चित ही आधुनिक शिक्षा और संस्कारहीनता ही इसके मूल में है। जिस देश में शक्ति की प्रतीक दुर्गा और काली की उपासना की जाती हो, उसी देश में आज बलात्कार, अपहरण और गायब होने की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ने लगी हैं? शासन-प्रशासन को इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करना होगा।

भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों को नई गति

प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर स्टॉकर के बीच व्यापक वार्ता

संवाददाता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस उच्चस्तरीय बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित एवं स्वच्छ तकनीक, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, मोबिलिटी और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय रिश्तों के पूरे दायरे की समीक्षा की गई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, इस बैठक में रक्षा, तकनीक, व्यापार, नवाचार, कौशल विकास और काउंटर-टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में कुल 15 ठोस परिणाम सामने आए। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से हाई-टेक्नोलॉजी सहयोग को भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी का केंद्रीय स्तंभ माना। प्रधानमंत्री ने चांसलर के सम्मान में एक लंच होस्ट किया। ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दौरे पर खास ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि आज हैदराबाद हाउस में उन्होंने आपसी रिश्तों के सभी पहलुओं पर बात की और साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच छह महत्वपूर्ण समझौते, एमओयू और लेटर ऑफ इंटेंट का आदान-प्रदान किया गया। इनमें ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन, फूड सेफ्टी एवं मानकों पर सहयोग, निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म की स्थापना और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग सेंटर और ऑस्ट्रियन आर्म्ड फोर्सेज इंटरनेशनल सेंटर के बीच साझेदारी की घोषणा भी की गई। दोनों पक्षों ने साल 2026 में वियना में संयुक्त स्पेस इंडस्ट्री सेमिनार आयोजित करने और वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम शुरू करने की भी घोषणा की। यह कदम युवाओं और पेशेवरों के बीच संपर्क बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। सचिव (पश्चिम) ने कहा कि वार्ता के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इसके खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने हाल के आतंकी हमलों की भी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि काउंटर-टेररिज्म सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति जताई। यह समूह सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और उभरती तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करेगा। नेताओं ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने और यूनाइटेड नेशंस तथा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे मंचों पर सक्रिय सहयोग जारी रखने का संकल्प दोहराया। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा कि चांसलर स्टॉकर की यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि चार दशकों में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर का यह पहला भारत दौरा है और यह दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुनना ऑस्ट्रिया की भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चांसलर स्टॉकर ने भी भारत के प्रति अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए एक्स पर कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की 75 वर्षों से अधिक पुरानी मित्रता में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में समान मूल्यों पर आधारित साझेदारियां और अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संभावित प्रभावों पर भी चर्चा की। उनका मानना है कि इस समझौते के लागू होने से व्यापार, विनिर्माण, निवेश और विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उल्लेखनीय है कि चांसलर स्टॉकर 14 से 17 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। चांसलर बनने के बाद यह उनकी एशिया की पहली यात्रा है, जो भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

स्मृति ईरानी-शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी ने की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत

संवाददाता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता स्मृति ईरानी, शुभेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि 15 अप्रैल को भाजपा नेताओं ने 'मातृशक्ति भरोसा कार्ड' नामक एक नई योजना की घोषणा की। इसके तहत महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में देने का वादा किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर इस योजना के फॉर्म भी बांटे जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की घोषणाएं और फॉर्म वितरण चुनाव आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन हैं। पार्टी के अनुसार, महिलाओं को इस योजना के तहत प्रलोभन देकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और इसके बदले नकद या प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के जरिए आर्थिक लाभ देने की बात कही जा रही है। पार्टी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का समय, तरीका और स्वरूप यह दर्शाता है कि यह कोई सामान्य या परोपकारी पहल नहीं है, बल्कि चुनाव के नजदीक सुनियोजित तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। उल्लेखनीय है कि, बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोलकाता में मौजूद थीं, जहां उन्होंने महिलाओं के बीच 'मातृशक्ति भरोसा कार्ड' का वितरण भी किया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना के खिलाफ हैं और इससे मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद प्रभावित होती है, साथ ही चुनावी मैदान में बराबरी का स्तर भी बिगड़ता है।

एल.आई.सी

भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।

-भारत सिंह

मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

आज का राशिफल

मेषः मेहनत का फल मिलेगा। सामाजिक कार्य करने में रुचि रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। कारोबार मनोनुकूल लाभ देगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से परिचय बढ़ेगा। शारीरिक कष्ट संभव है। अज्ञात भय सताएगा। चिंता तथा तनाव रहेंगे। किसी मनोरंजक यात्रा की योजना बनेगी। बुरे लोगों से दूर रहें।

वृषभः दूर से सुखद सूचना मिल सकती है। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यय होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। बड़ा काम करने का मन बनेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। बुद्धि का प्रयोग करें। लाभ बढ़ेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

मिथुनः नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति पर व्यय होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। नए मित्र बनेंगे। नया उपक्रम प्रारंभ करने की योजना बन सकती है। व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शुभ समय।

कर्कः पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है। विवाद को बढ़ावा न दें। किसी व्यक्ति के उकसाने में न आएं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भावना में बहकर न करें। बुद्धि का प्रयोग लाभ में वृद्धि करेगा। आय बनी रहेगी। थकान महसूस होगी।

सिंहः परिवार तथा मित्रों के साथ कोई मनोरंजक यात्रा का आयोजन हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने का योग है। मित्रों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे। नया कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रशंसा प्राप्त होगी। समय अनुकूल है। आलस्य त्यागकर प्रयास करें।

कन्याः कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है। योजना फलीभूत होगी। कारोबार में वृद्धि पर विचार हो सकता है। नौकरी में अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे। मातहतों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। व्यापार में मनोनुकूल लाभ होगा। उत्साह व प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभ समय।

तुलाः किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की आयोजना हो सकती है। सत्संग का लाभ मिलेगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। घर-बाहर सुख-शांति रहेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन सहायता प्राप्त होगी। धन प्राप्ति में बाधाएं दूर होंगी। ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा व्यय हो सकता है।

वृश्चिकः चोट व दुर्घटना से हानि संभव है। लापरवाही न करें। किसी व्यक्ति से व्यर्थ विवाद हो सकता है। मानसिक क्लेश होगा। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। आय में कमी हो सकती है। व्यापार ठीक चलेगा। लोगों से अधिक अपेक्षा न करें।

धनुः जल्दबाजी से काम बिगड़ेंगे तथा समस्या बढ़ सकती है। विरोध होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। बाहर जाने की योजना बनेगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग कार्य में आसानी देगा। घर-बाहर सुख-शांति बने रहेंगे। नौकरी में चैन रहेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा।

मकरः भूमि, भवन, दुकान, शोरूम व फैक्टरी इत्यादि की खरीद-फरोख्त हो सकती है। बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। विवाद को बढ़ावा न दें। कुसंगति से बचें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। धन प्राप्ति सुगम होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

कुंभः कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। कोई मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। जल्दबाजी से हानि संभव है। शरीर कष्ट से बचें।

मीनः दूसरे से अधिक अपेक्षा करेंगे। जल्दबाजी से काम में बाधा उत्पन्न होगी। दौड़धूप अधिक रहेगी। बुरी सूचना मिल सकती है, धैर्य रखें। बनते कामों में देरी होगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। मित्रों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। नौकरी में कार्यभार रहेगा। आय में निश्चितता रहेगी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: याचक से नायक बनने की ओर अग्रसर महिलाएं

अंजनी सक्सेना

भारत का लोकतंत्र एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। दशकों से लंबित महिला आरक्षण का सपना अब साकार होता दिख रहा है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति, सामाजिक संरचना और सत्ता संतुलन में एक गहरे बदलाव का संकेत है। यह वह क्षण है, जब देश की आधी आबादी जो अब तक निर्णय प्रक्रिया में सीमित भूमिका निभा रही थी वह अब सत्ता के केंद्र में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वहीं मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में इस कानून को लेकर जो सक्रियता और राजनीतिक वातावरण तैयार किया जा रहा है, वह इसे जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने की मंशा को दर्शाता है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा की वरिष्ठ महिला नेता अर्चना चिटनीस ने इसे "देश का भाग्य बदलने वाला कानून" बताया, जो इस अधिनियम की व्यापकता और महत्व को स्पष्ट करता है। महिला आरक्षण का मुद्दा न तो नया है और न ही आज का है। स्वतंत्रता के बाद से ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग समय-समय पर उठती रही। 1990 के दशक में यह मुद्दा गंभीर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक लाने का प्रयास हुआ लेकिन उस समय राजनीतिक सहमति के अभाव और विरोध के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। इसके बाद भी कई सरकारों ने इस विषय को अपने एजेंडे में शामिल किया, लेकिन ठोस परिणाम सामने नहीं आए। यही कारण है कि वर्तमान सरकार इस अधिनियम को केवल विधायी सफलता नहीं, बल्कि दशकों की प्रतीक्षा के अंत के रूप में प्रस्तुत कर रही है। सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को बहुआयामी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया गया है। पहले चरण में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। अब दूसरा चरण राजनीतिक सशक्तिकरण का है, जिसमें महिलाओं को सीधे सत्ता और नीति निर्माण में भागीदारी दी जा रही है।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यह कदम केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीति की दिशा और प्राथमिकताओं को भी बदलने की क्षमता रखता है। मध्यप्रदेश इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में नगरीय निकायों में पहले से ही महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व इससे भी अधिक, लगभग 54 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है, तो वे न केवल भागीदारी करती हैं, बल्कि नेतृत्व में भी आगे आती हैं। अर्चना चिटनीस का भी कहना है कि यह अधिनियम महिलाओं को "याचक नहीं, बल्कि नायक" बनाएगा। यदि यह कथन केवल राजनीतिक बयान नहीं है तो यह एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के संकेत दे रहा है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का सबसे बड़ा प्रभाव नीति निर्माण पर पड़ेगा। यह माना जाता है कि महिलाएं अधिक संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण के साथ निर्णय लेती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। इससे शासन की गुणवत्ता में सुधार होगा और नीतियों का प्रभाव अधिक व्यापक और संतुलित होगा। यह अधिनियम सामाजिक न्याय की उस अवधारणा को भी मजबूत करता है, जिसमें हर वर्ग और हर लिंग को समान अवसर मिले। हालांकि इस अधिनियम को लेकर राजनीतिक सहमति पूरी तरह एक जैसी नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लागू करने में देरी की जा रही है। वहीं भाजपा का तर्क है कि यह प्रक्रिया आवश्यक है ताकि आरक्षण का लाभ सही और संतुलित तरीके से सभी क्षेत्रों तक पहुंच सके। भाजपा नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने दशकों तक महिला आरक्षण को केवल चुनावी मुद्दा बनाए रखा, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे वास्तविकता में बदलने का काम किया। वैसे भी शाहबानो प्रकरण जैसे उदाहरणों के माध्यम से कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' का विजन महिलाओं की भागीदारी के बिना अधूरा है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। सेना, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति और उद्यमिता में उनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। देश में महिला राष्ट्रपति, महिला मुख्यमंत्री और अनेक महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि भारत अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां महिलाओं का नेतृत्व सामान्य बात बनता जा रहा है। ऐसे में संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना समय की मांग भी है और लोकतंत्र की आवश्यकता भी। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। जब बड़ी संख्या में महिलाएं संसद और विधानसभाओं में पहुंचेंगी, तो राजनीतिक विमर्श का स्वरूप भी बदलेगा। मुद्दों की प्राथमिकता बदलेगी, निर्णय लेने की शैली बदलेगी और शासन की संवेदनशीलता बढ़ेगी। मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में, जहां पहले से ही महिलाओं को व्यापक अवसर दिए जा रहे हैं, वहां यह बदलाव और तेजी से दिखाई देगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य इस परिवर्तन का अग्रदूत बन सकता है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक विकास का नया अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इसे आगे बढ़ाने की पहल यह दर्शाती है कि अब महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता बन चुका है। यह अधिनियम उस भारत की नींव रखेगा, जहां महिलाएं केवल मतदाता नहीं, बल्कि नीति निर्धारक होंगी, केवल सहभागी नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता होंगी। जब देश की आधी आबादी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगी, तो भारत का विकास भी दोगुनी गति से होगा। आने वाले वर्षों में यह कानून भारतीय राजनीति और समाज दोनों को नई दिशा देगा। एक ऐसी दिशा, जहां समानता, अवसर और नेतृत्व का संतुलन वास्तविक रूप में दिखाई देगा। यही 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का वास्तविक उद्देश्य और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

महाराष्ट्र में निवेश से उद्योगों का नया दौर शुरू : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

संवाददाता

मुंबई। राज्य में निवेश आकर्षित कर उसे उद्योगों में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा कई नीतिगत सुधार किए गए हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास का नया दौर शुरू हो गया है। यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही। उन्होंने कहा कि श्याम स्टील और जेडब्ल्यू ग्लोबल जैसे उद्योग समूहों का राज्य में निवेश इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने 'वर्षा' निवास स्थान पर आयोजित बैठक में उद्योग विभाग के साथ इन दोनों कंपनियों के साथ सामंजस्य करार (MoU) किए जाने के अवसर पर कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध करा रही है। उन्होंने निवेशकों से महाराष्ट्र में निवेश करने का आह्वान भी किया।

उन्होंने बताया कि जेडब्ल्यू ग्लोबल के माध्यम से राज्य में शाश्वत ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में निवेश की अनुमति मिलने के बाद महाराष्ट्र ने 'स्मॉल मॉड्युलर न्यूक्लियर रिएक्टर' में निवेश की दिशा में पहल की है और इस संबंध में दो समझौते भी किए गए हैं। विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल स्थित श्याम स्टील समूह चंद्रपुर जिले के गोडपिंपरी तालुका में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश कर स्टील उद्योग स्थापित कर रहा है, जिससे लगभग 8,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

वहीं, जेडब्ल्यू ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड राज्य में करीब 1.65 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। सोलापुर जिले के उजनी बांध में फ्लोटिंग सोलर पावर और एनर्जी स्टोरेज परियोजना के तहत कंपनी 14,976 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे लगभग 500 स्थायी रोजगार उत्पन्न होंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपस, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और स्मॉल मॉड्युलर न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया जाएगा, जिससे कुल मिलाकर लगभग 3,000 रोजगार सृजन की संभावना है। बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, सह सचिव लक्ष्मीकांत ढोके, मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धवसे सहित श्याम स्टील के अध्यक्ष पुरुषोत्तम बेरीवाला, प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ बेरीवाला तथा जेडब्ल्यू ग्लोबल के अध्यक्ष जयदीप वानखेड़े और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ठाणे में मेयर की मौजूदगी में चला मेगा सफाई अभियान, हटाया गया 10 टन कचरा

दिनेश चंद्र रावल

ठाणे। ठाणे के वर्तक नगर प्रभाग समिति अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में मेयर शर्मिला पिंपळोलकर की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत वसंत विहार सर्कल, नलपाड़ा, खेवरा सर्कल, हैप्पी वैली सर्कल, मानपाड़ा सिग्नल, टिकुजिनी वाडी रोड समेत आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई की गई और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया।

इस दौरान नगरसेवक मुकेश मोकाशी, डिप्टी कमिश्नर दिनेश तायडे और मधुकर तायडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। यह अभियान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कॉन्सेप्ट के तहत पूरे शहर में चलाया जा रहा है, जिसे मेयर के मार्गदर्शन में सभी वार्डों में लागू किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत सफाई शपथ के साथ की गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग की ओर से करीब 150 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया था।

सफाई कार्य के लिए दो जेटिंग मशीन, टॉयलेट सैनिटेशन वाहन, जेसीबी, डंपर और 10 बेल ट्रक सहित कई मशीनों का उपयोग किया गया।

इस दौरान कुल लगभग 10 टन कचरा और मिट्टी हटाई गई। अभियान में गार्डन, एनक्रोचमेंट, फाइलेरिया और कंस्ट्रक्शन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे। चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर मयूरी वखारिया, डिप्टी चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर लक्ष्मण पुरी, हेमंत चौधरी और इंजीनियर रणधीर समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। स्थानीय नागरिकों ने भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने कहा कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से इस तरह के बड़े सफाई अभियान चलाए जाएंगे।

मंत्री हसन मुश्रीफ ने मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के दिए निर्देश, देरी पर सख्त कार्रवाई के संकेत

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से अलिबाग, नंदुरबार, गोंदिया, सातारा और सिंधुदुर्ग में बन रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने की। बुधवार को मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, निधि वितरण, मानव संसाधन योजना और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन किया गया। मंत्री मुश्रीफ ने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ये मेडिकल कॉलेज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।

उन्होंने बताया कि कुछ परियोजनाओं में प्रगति संतोषजनक है, लेकिन कुछ स्थानों पर कार्य में देरी हो रही है। विशेष रूप से सिंधुदुर्ग के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मंत्री मुश्रीफ ने अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण, छात्रों के लिए छात्रावास और प्राध्यापकों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का स्तर ऊंचा होगा और चिकित्सा शिक्षा के अवसरों में भी वृद्धि होगी। बैठक में अनिल भंडारी, संदीप ढाकणे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि संबंधित मेडिकल कॉलेजों के अधिष्ठाता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

सतीस पूल प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों को राहत

ठाणे में नए घरों की चाबियां वितरित

संवाददाता

ठाणे। ठाणे के कोपरी डिवीजन स्थित न्यू इंदिरानगर इलाके में सतीस पूल प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पहल और सांसद नरेश म्हस्के के लगातार फॉलो-अप के चलते प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रभावित परिवारों को एक्मे, खेवरा सर्कल और मानपाड़ा क्षेत्रों में नए घर दिए गए हैं। बुधवार को टेंभिनाका स्थित आनंदाश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सांसद नरेश म्हस्के, मेयर शर्मिला पिंपलोलकर और नगरसेविका मालती पाटिल की उपस्थिति में मेयर हॉल में घरों की चाबियां वितरित की गईं।गौरतलब है कि रेलवे प्रशासन की कार्रवाई के चलते न्यू इंदिरानगर क्षेत्र के निवासियों में भय का माहौल था। इस दौरान नगरसेविका मालती पाटिल, नम्रता पमनानी और नगरसेवक भरत चव्हाण ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया और उनके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयास किए। कार्यक्रम में सांसद नरेश म्हस्के ने 10 प्रभावित परिवारों को स्वयं चाबियां सौंपीं, जबकि अन्य परिवारों को मेयर शर्मिला पिंपलोलकर, हाउस लीडर हनमंत जगदाले, नगरसेवक राम रेपाले और नगरसेविका मालती पाटिल ने चाबियां वितरित कीं। इस अवसर पर रोहित पिंपलोलकर, रमाकांत पाटिल, संतोष सतकर, विकास पाटिल सहित कई स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। प्रभावित परिवारों ने पुनर्वास के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

महाराष्ट्र में किरायेदारों को राहत हाईकोर्ट ने बदले नियमों के मायने

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र में किरायेदारी और मालिकाना हक के पेचीदा कानूनी विवादों के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो राज्य के हजारों किरायेदारों के लिए राहत की बड़ी खबर लेकर आया है। न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई किरायेदार उस संपत्ति का कानूनी रूप से कुछ हिस्सा खरीद लेता है जिसमें वह रह रहा है, तो उसे अब किरायेदार मानकर बेदखल नहीं किया जा सकता है। यह कानूनी विवाद दक्षिण मुंबई की एक पुरानी संपत्ति से शुरू हुआ था। इस मामले में एक व्यक्ति लंबे समय से एक मकान में किरायेदार के तौर पर रह रहा था। विवाद तब गहराया जब उस किरायेदार ने संपत्ति के मूल मालिकों में से एक के साथ कानूनी समझौता कर उस संपत्ति का कुछ हिस्सा खरीद लिया। इसके बाद, संपत्ति के अन्य सह-मालिकों ने आपत्ति जताई और उसे अब भी केवल एक 'कि किरायेदार' मानते हुए घर से बाहर निकालने (बेदखली) के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने इस कानूनी लड़ाई में तीन अलग-अलग किरायेदारों को पक्षकार बनाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जिस व्यक्ति को बेदखल करने की कोशिश की जा रही थी, उसने कानूनी कार्यवाही के दौरान ही संबंधित संपत्ति में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा खरीद लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जैसे ही कोई किरायेदार संपत्ति में स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसका 'कि किरायेदार' होने का दर्जा कानूनन समाप्त हो जाता है। इसके बाद वह उस संपत्ति का सह-स्वामी माना जाता है।

राज्य में बढ़ेगी गर्मी, 'दिलखुलास' कार्यक्रम में दी जाएगी सावधानी की जानकारी

संवाददाता

मुंबई। राज्य में आगामी दिनों में गर्मी की तीव्रता बढ़ने की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। इस पृष्ठभूमि में नागरिकों को सतर्क करने और लू से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय द्वारा निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रम में गर्मी से बचाव, सावधानियां और राज्य सरकार द्वारा तैयार मानक कार्यपद्धति (SOP) की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यह विशेष कार्यक्रम शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को सुबह 7:25 से 7:40 बजे तक आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर प्रसारित होगा। साथ ही News On AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम का संचालन सुषमा जाधव ने किया है। देश के सबसे अधिक गर्मी प्रभावित 10 राज्यों में महाराष्ट्र का भी समावेश है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से डिलीवरी कर्मचारी, मजदूर और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सुरक्षा के लिए मानक कार्यपद्धति में महत्वपूर्ण उपाय शामिल किए गए हैं। तीव्र गर्मी के दौरान दिन में काम करने वाले श्रमिकों के लिए तीन अलग-अलग SOP तैयार की गई हैं, जो छह महीने के गहन अध्ययन पर आधारित हैं। इनमें असंगठित कामगार, खदान मजदूर और गर्मी सहन करने वाले आवासीय ढांचे से जुड़े उपाय शामिल हैं। अप्रैल, मई और जून के दौरान जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। 'दिलखुलास' कार्यक्रम के जरिए नागरिकों को इस अवधि में अपनाई जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

आदित्य ठाकरे पर बेबुनियाद आरोप से भड़की प्रियंका चतुर्वेदी

संवाददाता

मुंबई। संसद के नए भवन में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चल रही ऐतिहासिक चर्चा आज उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच निजी हमलों और तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी बात रखते हुए शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने जब भाजपा के पूर्व विधायक और दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सेंगर तथा बृज भूषण सिंह का मुद्दा उठाया, तो सदन का माहौल गरमा गया। इसके जवाब में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र के युवा नेता आदित्य ठाकरे का नाम लेकर एक गंभीर और बेबुनियाद आरोप मढ़ दिया, जिससे महा विकास अघाड़ी के सांसद आक्रोशित हो गए।

सांसद अरविंद सावंत ने महिला सुरक्षा के सवाल पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि क्या अपराधियों को संरक्षण देना ही नारी शक्ति का सम्मान है? उन्होंने कहा कि आरक्षण से पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले नेताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी दौरान निशिकांत दुबे ने हस्तक्षेप करते हुए आदित्य ठाकरे का नाम लिया और उन पर एक अभिनेत्री की मौत से जुड़ा आपत्तिजनक आरोप लगाया। इस टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। सावंत और सुप्रिया सुले ने तुरंत खड़े होकर इसका कड़ा विरोध किया और याद दिलाया कि आदित्य ठाकरे इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं, इसलिए उनका नाम लेना संसदीय मर्यादा के खिलाफ है।

शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस घटना पर एक वीडियो संदेश जारी कर भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि एक सजायाफ्ता बलात्कारी (कुलदीप सेंगर) का बचाव करने के लिए भाजपा सांसद एक ऐसे नेता पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जो सदन में अपना बचाव करने के लिए मौजूद भी नहीं है। प्रियंका ने इसे भाजपा की हताशा करार देते हुए मांग की कि निशिकांत दुबे को अपने अनर्गल और सनसनीखेज आरोपों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

हंगामे के दौरान अरविंद सावंत ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने निशिकांत दुबे को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो विपक्ष भी 'गोधरा कांड' और 'तड़ीपार' जैसे पुराने विवादों को कुरेदने से पीछे नहीं हटेगा।

सावंत ने अमित शाह का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और चेतावनी दी कि यदि उन्होंने अपना मुंह खोला तो सत्ता पक्ष के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सदन में बढ़ते तनाव को देखते हुए स्पीकर से इन विवादित टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने की मांग की गई।

विवादों के बीच अरविंद सावंत ने महिला आरक्षण विधेयक की तकनीकी खामियों पर भी प्रहार किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यदि मंशा साफ है, तो मौजूदा 544 सीटों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का साहस क्यों नहीं दिखाया जा रहा? निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन (परिसीमन) के जरिए सांसदों की संख्या बढ़ाकर आरक्षण देने की योजना को उन्होंने एक राजनीतिक चाल बताया। सावंत ने जोर देकर कहा कि विपक्ष आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि परिसीमन के नाम पर होने वाले क्षेत्रीय असंतुलन और देरी के खिलाफ है।

बांद्रा पूर्व में 'नियोजन भवन' का भूमिपूजन, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा परिसर

संवाददाता

मुंबई। बांद्रा पूर्व स्थित मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर में गुरुवार को बनने वाले 'नियोजन भवन' का भूमिपूजन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुंबई उपनगर के पालकमंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार ने भूमिपूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। समारोह में विधायक संजय उपाध्याय, जिलाधिकारी सौरभ कटियार, जिला नियोजन अधिकारी संजय शिंदे सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम से पूर्व सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा ने भूमि पूजन किया। बांद्रा (पूर्व) स्थित जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर में बनने वाला यह 'नियोजन भवन' एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य जिला नियोजन समिति के कार्यों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र सरकार के नियोजन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में स्वतंत्र नियोजन भवन निर्माण की योजना के तहत यह परियोजना शुरू की गई है।

इस परियोजना को 19 नवंबर 2025 को लगभग 741.04 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिली थी, जबकि 6 फरवरी 2026 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। कुल 1031.25 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाली इस इमारत का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में भूतल और एक मंजिल की मुख्य इमारत बनाई जाएगी, जिसमें 300 सीटों की क्षमता वाला सभागार, दो ग्रीन रूम, किचन व पैंट्री तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं होंगी। पहली मंजिल पर जिला नियोजन समिति का कार्यालय और एक छोटा सभागार भी बनाया जाएगा। दूसरे चरण में इमारत की आंतरिक सजावट, सभागार का साउंडप्रूफिंग, फॉल्स सीलिंग, दरवाजे, फर्नीचर और अन्य पूरक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंत्री शेलार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को निर्धारित समय में पूरा किया जाए।

Chandigarh School Receives Bomb Threat via Email, Security Agencies Launch Massive Search

CHANDIGARH: Panic gripped the city after a bomb threat was reported at a school in Sector-32. The threat, sent via email, triggered an immediate response from police, bomb disposal squads, and fire brigade teams, who rushed to the spot and cordoned off the premises to initiate a thorough search operation. At the time of the incident, students were in their classrooms following morning prayers. The sudden arrival of a heavy police presence caused anxiety among students and staff. However, officials urged everyone to remain calm and cooperate. As a precautionary measure, security was heightened both inside and outside the school campus.

Police and bomb disposal teams carried out an extensive search of the entire campus, including classrooms, corridors, parking areas, store rooms, and open spaces. Advanced equipment is being used to detect any suspicious objects. Fire brigade teams have also been deployed at the site to handle any emergency. Additional police personnel have been stationed outside the school, closely monitoring movement in the surrounding area.

Preliminary investigations indicate that the threat was sent via email. The police cyber team is working to trace the sender's identity and location. Officials stated that the matter is being treated with utmost seriousness and is being investigated from all angles. Notably, several government and private schools in Chandigarh have received similar bomb threats via email in the past. Threats have also been sent to institutions such as the passport office, post office, Punjab Secretariat, High Court, and district courts. Although no explosives were found in earlier cases, security agencies have consistently conducted thorough checks with heightened vigilance.

BENGAL POLLS: EC ORDERS BAMBOO BARRICADING AT BOOTHS WITHOUT BOUNDARY WALLS

KOLKATA: In a move aimed at ensuring free and fair elections in West Bengal, the Election Commission of India has issued key directives to strengthen security at vulnerable polling stations. The Commission has instructed authorities to erect temporary bamboo barricades around booths that lack permanent boundary walls to prevent unauthorized access.

According to a source in the office of the Chief Electoral Officer, several polling stations—many located within school premises have been identified during inspections as lacking proper enclosures. This raises concerns that outsiders could bypass security surveillance by central armed police forces deployed at these locations.

The issue is particularly acute in remote and forested areas, where polling stations are surrounded by dense vegetation or open terrain, increasing the risk of security breaches. Taking this into account, the Commission has directed that such booths be secured with bamboo fencing, along with the deployment of additional security personnel to ensure strict monitoring and control of entry points.

The Commission has also issued specific instructions to Booth Level Officers, directing them to distribute voter slips door-to-door, similar to the recently concluded Special Intensive Revision exercise. It has clearly stated that under no circumstances should this responsibility be delegated to representatives of any political party.

Ahead of the first phase of polling, sector officers, presiding officers, and other election staff have been given strict guidelines to maintain neutrality. They have been instructed not to seek or accept any assistance from political parties or their agents during the polling process.

Additionally, election personnel have been advised against accepting food, water, or any other items from political representatives, and instead rely solely on arrangements made by the administration.

Polling in West Bengal will be conducted in two phases on April 23 and April 29, with counting of votes scheduled for May 4.

Post devastating Lucknow inferno, 2 toddlers killed

LUCKNOW: Two children were killed in a major fire that torched a slum cluster in the Vikas Nagar area of district here on Thursday, police said, as rescue workers and villagers combed through the scene, which had been turned to ashes by the flames the night before. The deaths of two toddlers, both approximately two years old, were found late Wednesday, hours after the horrific fire broke out, according to Deputy Commissioner of Police (East) Deeksha Sharma. The bodies have been submitted for a post-mortem. Their parents have been

notified, and the identification procedure is already ongoing, she said. The fire broke out Wednesday evening in a slum cluster along the Ring Road in Vikas Nagar, quickly engulfing roughly 200 shanties and reducing people' valuables to ashes. Hundreds of individuals, largely domestic workers and daily wage earners, were made homeless.

After getting information about the incident, fire trucks were quickly dispatched to the scene, and rescue and relief efforts were launched without delay, according to Sharma. Teams from the police, fire department, SDRF, and NDRF have been sent to the location since Wednesday evening, she added, adding that the rescue effort continued late into the night. According to officials, the fire destroyed over 200 shanties, displacing hundreds of inhabitants, the majority of whom are domestic workers and daily wage earners. Defence Minister Rajnath Singh and Samajwadi Party head Akhilesh Yadav voiced their worry at the event, calling for urgent assistance and a thorough inquiry. Authorities stated the cause of the fire has yet to be determined. Hundreds of inhabitants returned to the charred ruins of their homes in the Vikas Nagar slum cluster on Thursday morning, sifting through the ashes in a desperate quest for valuables, only to discover that practically everything had been gone. Men, women, and children were spotted rummaging through layers of smoke and rubble, trying to find their belongings, but the majority returned empty-handed when the magnitude of damage became clear in daylight. Kuch na bacha, sab bar gawa (Nothing is left, everything is gone in fire), the woman cried in Awadhi, breaking down as she dug through the ruins of her destroyed cottage. The scene was littered with burned steel closets, twisted trunks, wrecked bicycles, charred kitchenware, gas burners, and strewn garments, as well as half-burnt vegetables within kitchen racks. Coolers, pedestal fans, and even refrigerators were discovered gutted. A strong odor of smoke persisted, and some debris continued to produce fumes. When a refrigerator was opened, there were still indications of fire within. Many people suffered not just pecuniary losses, but also severely personal ones. Deepa, a domestic worker, explained that she had meticulously collected money over the years to create her home. I had gathered everything piece by piece. Nothing remains, she said. Another woman stated she had some money and jewelry.

भारताचा आत्मा भारतीय भाषांमधूनच व्यक्त होतो : राष्ट्रपती

वर्धा: भारताचा आत्मा भारतीय भाषांमधूनच व्यक्त होतो. विविध भारतीय भाषांमधून संस्कृती, संवेदनशीलता आणि चेतनेचा एकच प्रवाह वाहत असतो, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात वर्धा इथल्या महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयात आज त्यांच्या उपस्थितीत, सहावा दीक्षांत समारंभ झाला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. ईशान्य भागातील विद्यार्थ्यांसह देशभरातील विविध राज्यांमधील विद्यार्थी महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत हे पाहून आपल्याला आनंद झाला, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. आंतरभाषिक संवादाची ही परंपरा हिंदीसह सर्व भारतीय भाषांच्या प्रगतीस हातभार लावेल असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

राष्ट्रपतींनी विद्यार्थ्यांना आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगण्याचा सल्ला दिला. राष्ट्राविषयीच्या अभिमानाच्या भावनेसह, दोन राष्ट्रीय उद्दिष्टांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे, असे सांगत, ही उद्दिष्टे भारतीयत्वशी जोडलेली आहेत , आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेशी जोडलेली आहेत आणि आपल्या देशबांधवांची, विशेषतः युवकांची प्रतिभा व आत्मविश्वास यांच्याशी अविभाज्यपणे जोडलेली आहेत, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. ती उद्दिष्टे म्हणजे वसाहतवादी मानसिकतेचा मागमूस नष्ट करणे आणि भारतीय ज्ञान परंपरेची पुनर्स्थापना करणे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही भाषेला विरोध न करण्याचा परंतु भारतीय भाषांचा अभिमान बाळगण्याचा सल्ला दिला.

या विद्यापीठाला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे नाव देणे हे सर्वार्थाने उचित आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या विद्यापीठाशी संबंधित असलेले सर्वजण, हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांच्या संवर्धन आणि विकासासाठी दृढ निश्चयाने काम करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बापूंच्या आदर्शांचे पालन करून, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयाशी निगडित तुम्ही सर्वजण विद्यापीठाचा गौरव निरंतर वाढवाल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

गांधीजींनी शिक्षणाला स्वावलंबनाचा पाया मानले. गांधीजींच्या म्हणण्यानुसार केवळ बहुसंख्य नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजांशी जोडलेले शिक्षणच अर्थपूर्ण शिक्षण म्हणता येईल, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. राष्ट्रीय हित साध्य न करणाऱ्या शिक्षणाला गांधीजींनी 'अराष्ट्रीय शिक्षण' असे संबोधले आणि अशा शिक्षणावर त्यांनी टीका केली होती. लोकांच्या भावना समजून घेण्याची, सर्वसामान्यांच्या जीवनांमध्ये रस घेण्याची आणि त्यांच्या वतीने बाजू मांडण्याची क्षमता हा अर्थपूर्ण शिक्षणाचा एक अविभाज्य भाग आहे असे गांधीजी मानत असत.

गांधीजींचे शिक्षणाच्या बाबतीत असलेले विचार सुमारे 100 वर्षांपूर्वी जितके उपयुक्त होते तितकेच ते आजही प्रासंगिक ठरत आहेत यावर राष्ट्रपतींनी अधिक भर दिला.

केवळ आपली मातृभाषाच, सर्जनाची, अन्वेषण, अभिव्यक्ती तसेच नवोन्मेषाची भाषा म्हणून कार्य करू शकते, असे विचार मांडत, आपण केवळ नक्कल न करता अस्सल कार्याची निर्मिती केली पाहिजे.

धमकीचा ईमेल आल्यानंतर दिल्ली विधानसभा अध्यक्षांना 'झेड' श्रेणीची सुरक्षा

नवी दिल्ली: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांना सतत मिळत असलेल्या बॉम्ब धमक्या आणि अलीकडील सुरक्षा त्रुटीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना 'झेड' श्रेणीची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.

यासोबतच विधानसभा परिसराची सुरक्षा देखील पूर्णपणे कडक करण्यात येत आहे, जेणेकरून कोणतीही गडबड होऊ नये.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्षांची सुरक्षा वाढवत त्यांना ' झेड' श्रेणीचे सुरक्षा कवच देण्यात आले आहे.

हा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला, जेव्हा विधानसभा सचिवालय आणि अध्यक्षांच्या कार्यालयाच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर सुमारे ६ ते ७ धमकीचे ईमेल प्राप्त झाले. या ईमेलमध्ये बॉम्बस्फोटाची धमकी देण्यात आली होती. या धमक्यांव्यतिरिक्त अलीकडेच विधानसभा परिसरात एक मोठी

सुरक्षा त्रुटीही समोर आली होती.

एका व्यक्तीने विधानसभा गेट ओलांडून आत प्रवेश केला आणि अध्यक्षांच्या गाडीत एक संशयास्पद वस्तू ठेवून निघून गेला.

या घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली असून संपूर्ण व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला आहे.

नवीन सुरक्षा व्यवस्थेनुसार आता विजेंद्र गुप्ता यांच्या सोबत २४ तास विशेष सुरक्षा पथक तैनात राहील. त्यांच्या ताफ्यासोबत कायम एक एस्कॉर्ट वाहन असेल.

सुरक्षा पथकाची जबाबदारी एका प्रभारी अधिकाऱ्याकडे असेल, तर प्रशिक्षित कमांडोही सोबत असतील.

सार्वजनिक कार्यक्रम आणि अधिकृत दौऱ्यांदरम्यानही त्यांची सुरक्षा पूर्वीपेक्षा अधिक कडक राहील.

दरम्यान, दिल्ली विधानसभा परिसरातही मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा उपाययोजना केल्या जात आहेत.

सर्व प्रवेशद्वारांवर ऑटोमॅटिक बूम बॅरिअर्स बसवले जात आहेत, जेणेकरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती आणि वाहनांची तपासणी अनिवार्य होईल. बॅग आणि इतर सामानाचीही काटेकोर तपासणी केली जाईल. याशिवाय, परिसरात सीआरपीएफची क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) वाहनांसह तैनात करण्यात आली आहे. ही टीम सतत गस्त घालेल आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ कारवाई करेल.

लेबनॉन-इस्त्रायल तणाव शिगेला, हिजबुल्लाहचे 24 तासांत इस्त्रायलवर 39 हल्ल्यांचे दावे

बेरूत: लेबनॉनमधील सशस्त्र गट हिजबुल्लाहने दावा केला आहे की त्यांच्या लढवय्यांनी मागील 24 तासांत 39 लष्करी मोहिमा राबवल्या आहेत. या हल्ल्यांमध्ये इस्त्रायली वसाहती, सैनिकांच्या तुकड्या आणि लष्करी वाहनांना लक्ष्य करण्यात आले. तसेच दक्षिण सीमारेषेवर आणि उत्तर इस्त्रायलमध्ये दोन्ही बाजूंमध्ये समोरासमोर चकमकीही झाल्या.मीडिया अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी बुधवारी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. त्यांनी सांगितले की इस्त्रायली सैन्य दक्षिण लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहविरोधात आपले अभियान सुरू ठेवणार आहे. नेतान्याहू यांनी बिंट जबीलला हिजबुल्लाहचा मुख्य गड म्हटले असून तो पूर्णपणे नष्ट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.याच दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) चे प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस यांनी लेबनॉनमधील रुग्णालयांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की दक्षिण लेबनॉनमधील 'तेबनीन सरकारी रुग्णालय' गंभीर संकटात आहे. एप्रिल महिन्यात रुग्णालयाजवळ झालेल्या दोन वेगवेगळ्या हल्ल्यांमध्ये त्याचे मोठे नुकसान झाले. या घटनांमध्ये 11 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दुखापत झाली आहे.रुग्णालयातील आपत्कालीन विभाग, व्हेंटिलेटर, मॉनिटर्स आणि फार्मसीसारखी आवश्यक साधने निकामी झाली आहेत.

काही सेवा अजूनही सुरू असल्या तरी, टेड्रोस यांनी सांगितले की डब्ल्यूएचओ तातडीच्या गरजांनुसार आपत्कालीन दुरुस्तीमध्ये मदत करत आहे. डब्ल्यूएचओ प्रमुखांनी आरोग्य सेवांवरील हल्ल्यांचे आकडेही दिले. संघर्ष सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत आरोग्य सेवांवर 133 हल्ले झाले आहेत. यात 88 जणांचा मृत्यू झाला असून 206 जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यांमुळे 15 रुग्णालये आणि 7 आरोग्य केंद्रे नुकसानग्रस्त झाली आहेत.

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ

(म्हाडाचा घटक)

म्हाडा MHADA

जाहिर सुचना

मौजे- वांद्रे, ता-अंधेरी येथील न.भू.क्र.१४ (पै) या मिळकतीवरील गॅलेक्सी सह. गृह. संस्था (नियो.) या संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत परि-२ मधील अ.क्र. १२३ वरील श्रीम. हुसनाबानो तौहिद खान यांच्या ऐवजी श्री. मोहम्मद अफजल हिदायतउल्ला शेख यांचे नाव सामाविष्ट करून पात्रता निश्चित करणेकामीचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. सबब सदर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की, उपरोक्त प्रकरणी हरकत असल्यास ८ दिवसांत खालील सही करणार यांच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी, असे याद्वारे जाहिर असे.

पत्ता : कक्ष क्र.३११, दुसरा मजला,
गृहनिर्माण भवन, कलानगर,
वांद्रे (पूर्व), मुंबई -४०० ०५१

करीता/ -
सक्षम प्राधिकारी तथा भूव्यवस्थापक
मुंबई मंडळ

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १७/०४/२०२६

म्हाडा- गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य संस्था

'टोस्टर' बनी चर्चा में, एक्टिंग ने दर्शकों को किया इंप्रेस

मुंबई। नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी-ड्रामा 'टोस्टर' ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई है। इसमें राजकुमार राव और शनाया मल्होत्रा के अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है। दर्शक और इंडस्ट्री के लोग उनके अभिनय की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री सोहा अली खान की बहन सबा पटौदी ने भी फिल्म की जमकर सराहना की। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तस्वीर पोस्ट की। इसमें सोहा, राजकुमार राव और अर्चना पूरन सिंह भी नजर आ रही हैं। उन्होंने तस्वीर पोस्ट कर सभी की सराहना की। उन्होंने लिखा, 'एक शानदार फिल्म के लिए चियर्स।' उन्होंने लिखा, 'नेटफ्लिक्स पर आई यह फिल्म बहुत ही मजेदार और हल्की-फुल्की कॉमेडी से भरपूर है। इसे सभी अपने दोस्तों और परिवार के साथ आराम से बैठकर जरूर देख सकते हैं। यह देखने में बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं लगती।'

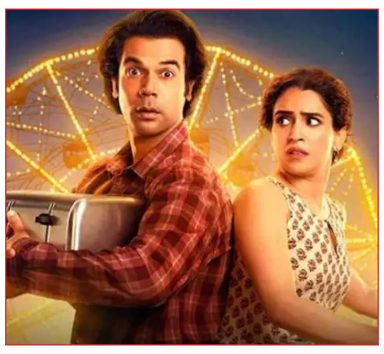

सबा ने फिल्म के सभी कलाकारों को जमकर सराहा। उन्होंने लिखा, 'पत्रलेखा, आप सच में एक हीरा हैं। राजकुमार, आप कमाल के कलाकार हैं और फिल्म में भी शानदार काम किया है। वहीं, शनाया, आप बेहतरीन हैं। अर्चना, आपने वाकई में शानदार काम किया और पूरी कास्ट और क्रू को भी बहुत-बहुत बधाई। आप सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है।'

'टोस्टर' एक डार्क कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें हंसी के साथ रोमांच भी है। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होने के कारण यह घर बैठे आसानी से देखी जा सकती है। फिल्म की कहानी एक कंजूस व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शादी में तोहफे में दिए गए 5,000 रुपए के टोस्टर को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, जिससे हास्यास्पद लेकिन भयावह घटनाएं होती हैं। निर्देशक विवेकदास चौधरी इस फिल्म से डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं और राजकुमार राव की पत्नी और अभिनेत्री पत्रलेखा के प्रोडक्शन हाउस 'कम्पा फिल्म' की यह पहली फिल्म है।

पत्रलेखा द्वारा निर्मित फिल्म 'टोस्टर' में अभिषेक बनर्जी, फराह खान, जितेंद्र जोशी, उपेन्द्र लिमये और सीमा पाहवा जैसे कलाकार भी हैं। यह फिल्म 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है।

जब अक्षय कुमार ने बचाई लारा दत्ता की जान

मुंबई। कभी-कभी फिल्मी दुनिया की चमक-दमक के पीछे ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। लारा दत्ता की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब फिल्म की शूटिंग के दौरान वह एक मुश्किल में फंस गईं, जिसमें उनकी जान जाते-जाते बची। लारा दत्ता का जन्म 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। उनके पिता भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर थे। उन्होंने बेंगलुरु से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ-साथ उनमें कुछ अलग करने की चाह भी थी, जिसने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मॉडलिंग में कदम रखते ही लारा दत्ता ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। साल 1997 में उन्होंने ग्लैडरैग्स प्रतियोगिता जीती। साल 2000 में उन्होंने

मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह भारत की दूसरी महिला बनीं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत के बाद वह पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं और उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए।

साल 2003 में लारा दत्ता ने फिल्म 'अंदाज' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा नजर आए। पहली ही फिल्म से उन्हें काफी सराहना मिली और बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने उस वक्त सभी को डरा दिया था।

फिल्म के एक गाने की शूटिंग समुद्र के किनारे हो रही थी। लारा को पानी से डर लग रहा था, लेकिन शूटिंग के लिए वह लहरों के बीच गईं। अचानक एक ऊंची लहर आई और उनका संतुलन बिगड़ गया। वह पानी के साथ बहने लगीं। उस समय वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए, लेकिन अक्षय कुमार ने बिना समय गंवाए समुद्र में छलांग लगा दी और अपनी जान की परवाह किए बिना लारा को सुरक्षित बाहर ले आए। यह घटना उनके लिए बहुत डरावनी थी, लेकिन इसी ने उनकी हिम्मत को और मजबूत किया।

अरिजीत से मिली गायकी की प्रेरणा : निकिता गांधी

मुंबई। बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपने बहुमुखी गायन से फैंस के दिलों में खास जगह बना चुकी निकिता गांधी ने अरिजीत सिंह के साथ कई गानों में अपनी आवाज दी है। उन्होंने हाल ही में आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि वे अरिजीत की बहुत बड़ी फैन हैं। निकिता कहती हैं, 'मैं अरिजीत की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं और मैं उनके सफर और गायकी का बहुत सम्मान करती हूं। मैं खुद भी एक बहुमुखी गायिका हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने उनके सफर से बहुत कुछ सीखा है। बेशक, इस बात का बहुत दुख है कि अभी वे नए दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारा काम किया है और इस इंडस्ट्री को अपना बहुत कुछ दिया है।' निकिता गांधी ने आगे अपने सफर को याद किया। उन्होंने बताया कि पहले फिल्मों में गाना शुरू किया, उसके बाद अपना इंडी म्यूजिक रिलीज किया। आमतौर पर लोग पहले इंडी करते हैं और फिर फिल्मों में आते हैं, लेकिन मेरा सफर उल्टा रहा। कॉलेज के दिनों में मैंने तमिल फिल्मों में गाना शुरू किया। उस समय म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन साउथ इंडस्ट्री और फिर बॉलीवुड में मौका मिला। उसके बाद उन्होंने अपना करियर शुरू किया। निकिता कहती हैं, 'यह बहुत अलग और शानदार सफर रहा, क्योंकि मैंने कभी सिंगर बनने का सपना नहीं देखा था। इसलिए, मैंने इसे प्यार से किया और अपने करियर का पूरा मजा लिया।' लाइव परफॉर्मेंस और स्टूडियो रिकॉर्डिंग के बीच अंतर पर बात करते हुए निकिता ने बताया कि दोनों अनुभव बिल्कुल अलग हैं। दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। लाइव शो में दर्शकों की मिली-जुली ऊर्जा मिलती है, जो बहुत खास होती है। वह पल उसी समय का होता है और चला जाता है। हर कोई उस अनुभव को महसूस करता है।

महंगे क्रीम नहीं, सोने का तरीका तय करता है त्वचा की उम्र

अक्सर लोग बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकने के लिए महंगे स्किनकेयर और एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती इन सभी कोशिशों पर पानी फेर सकती है? हालिया शोध के अनुसार, आपके सोने का तरीका या 'स्लीप पोजीशन' आपकी त्वचा की उम्र तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एस्थेटिक सर्जरी जर्नल की रिपोर्ट का खुलासा

'एस्थेटिक सर्जरी जर्नल' में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, जिस पोजीशन में आप सोते हैं, वह न केवल आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है, बल्कि आपके चेहरे पर असमय झुर्रियां भी ला सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि नींद के दौरान चेहरे पर पड़ने वाला दबाव त्वचा की बनावट को स्थाई रूप से बिगाड़सकता है।

कैसे पड़ते हैं चेहरे पर निशान?

जब हम साइड (करवट) या पेट के बल सोते हैं, तो हमारे चेहरे की त्वचा और तकिये के बीच सीधा संपर्क होता है।

इस दौरान स्किन पर तीन प्रकार के बल काम करते हैं:

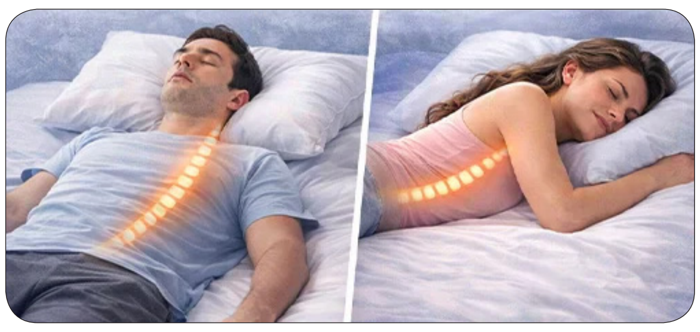

- **कम्प्रेशन:** चेहरे का तकिये से दबना।
- **टेंशन:** त्वचा का खिंचना।
- **शियर फोर्सेस:** त्वचा और कपड़े के बीच होने वाली रगड़।

विशेषज्ञों का कहना है कि 30 साल की उम्र के बाद शरीर में कोलेजन का स्तर कम होने लगता है। ऐसे में नींद के दौरान पड़ने वाली ये 'स्लीप लाइन्स' धीरे-धीरे गहरी झुर्रियों में तब्दील हो जाती हैं।

कौन सी पोजीशन है सबसे खतरनाक?

- **पेट के बल सोना:** इसे त्वचा के लिए सबसे बुरा माना गया है। इसमें चेहरा तकिये में धंसा रहता है, जिससे न केवल झुर्रियां पड़ती हैं बल्कि आंखों के नीचे सूजन (Puffiness) भी आ सकती है।
- **करवट लेकर सोना:** यह सबसे आम पोजीशन है, लेकिन इसमें गालों और ठुड्डी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जिस तरफ ज्यादा सोते हैं, चेहरे के उस हिस्से पर रेखाएं अधिक गहरी होती हैं।
- **पीठ के बल सोना:** झुर्रियों से बचने के लिए इसे 'गोल्डन रूल' माना गया है। इसमें चेहरा किसी भी सतह से नहीं टकराता, जिससे त्वचा सुरक्षित रहती है।

एक्सप्रेशन लाइन्स बनाम स्लीप रिंकल्स

अक्सर लोग स्लीप रिंकल्स को सामान्य उम्र बढ़ने वाली रेखाएं समझ लेते हैं। हालांकि, मुस्कुराने या भौहें सिकोड़ने से बनने वाली 'एक्सप्रेशन लाइन्स' मांसपेशियों के संकुचन से होती हैं, जबकि 'स्लीप रिंकल्स' बाहरी दबाव और खिंचाव का परिणाम होते हैं। अपनी सोने की आदत में बदलाव करके आप अपनी त्वचा को लंबे समय तक जवां रख सकते हैं।

ढाबे वाला स्वाद अब घर पर, बनाएं मसालेदार भरवां तंदूरी आलू

क्या आपको भी ढाबे का खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता है? खास तौर पर वो मसालेदार और भुने हुए तंदूरी आलू, जो बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं जिससे आप घर की साधारण कड़ाही में ही ढाबे जैसा भरवां तंदूरी आलू बना सकते हैं।

कितने लोगों के लिए : 4

सामग्री :

- छोटे आकार के आलू - 10-12
- पनीर - 1 कप (कद्दूकस किया हुआ)
- उबले हुए आलू का गूदा - आधा कप
- बारीक कटा प्याज - 1
- बारीक कटी हरी मिर्च - 1-2
- अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 चम्मच
- गरम मसाला - आधा चम्मच
- अमचूर पाउडर - आधा चम्मच
- नमक - स्वादानुसार, तेल - तलने के लिए
- गाढ़ा दही - आधा कप, बेसन - 2 चम्मच
- अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर - 1 चम्मच
- हल्दी पाउडर - आधा चम्मच, धनिया पाउडर - 1 चम्मच, जीरा पाउडर - आधा चम्मच
- गरम मसाला - आधा चम्मच, चाट मसाला - आधा चम्मच, कस्तूरी मेथी - 1 चम्मच
- सरसों का तेल - 1 चम्मच, नमक - स्वादानुसार

विधि :

- सबसे पहले छोटे आलू को 80% तक उबाल लें। ध्यान रखें कि ये पूरी तरह न पकें। ठंडा होने के बाद, इन्हें छील लें और बीच से चम्मच की मदद से थोड़ा गूदा निकाल लें ताकि स्टफिंग के लिए जगह बन जाए।
- अब एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर, निकाला हुआ आलू का गूदा, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को आलुओं के अंदर अच्छी तरह भर दें।
- फिर एक बड़े बाउल में दही, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले (लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला), कस्तूरी मेथी, गर्म सरसों का तेल और नमक डालकर अच्छे से फेंट लें।
- अब भरे हुए आलू को इस मैरिनेशन के मिश्रण में डालें और हर तरफ से अच्छी तरह लपेट दें। इन्हें कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि मसाले आलुओं के अंदर तक चले जाएं।
- एक भारी तले वाली कड़ाही में थोड़ा तेल या घी डालकर गर्म करें। आंच को धीमी रखें और इसमें मैरिनेट किए हुए आलुओं को सावधानी से रखें। इन्हें हर तरफ से पलट-पलटकर तब तक भूनें जब तक ये सुनहरे भूरे और हल्के जले हुए न दिखें। यही तो है ढाबे का असली स्वाद।
- आखिर में, गरमा-गरम तंदूरी आलुओं को कड़ाही से निकालें। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और बारीक कटी हरी धनिया डालकर परोसें। इन्हें हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें।

वीजा अप्लाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा रिजेक्शन

विदेश यात्रा जितनी रोमांचक हो सकती है, उसकी तैयारी उतनी ही मुश्किल। इसमें सबसे बड़ा और अहम पड़ाव वीजा अप्लाई करना है। किसी भी देश में जाने से पहले वहां का वीजा लेना काफी जरूरी है। लेकिन कई बार वीजा अप्लाई करते समय हम से कुछ चूक या जानकारी की कमी के कारण वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर वीजा अप्लाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानें इस बारे में।

पासपोर्ट की वैधता और खाली पन्ने

ज्यादातर देशों का नियम है कि आपके पासपोर्ट की वैधता आपकी यात्रा की तारीख से कम से कम 6 महीने आगे तक होनी चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट जल्द ही एक्सपायर होने वाला है, तो वीजा अप्लाई करने से पहले उसे रिन्यू करा लें। साथ ही, यह भी चेक करें कि आपके पासपोर्ट में कम से कम 2-3 खाली पन्ने हों, ताकि वीजा स्टैम्प लगाने के लिए जगह मिल सके।

सही वीजा कैटेगरी चुनें

अक्सर लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। अपनी यात्रा के मकसद को साफ रखें। आप घूमने जा रहे हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार से मिलने, हर कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट और नियम अलग होते हैं। गलत कैटेगरी में अप्लाई करने का सीधा मतलब है वीजा रिजेक्शन।

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी

एंबेसी यह जानना चाहती है कि आपके पास विदेश में रहने और वापस आने के लिए पैसे हैं या नहीं। इसके लिए पिछले 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न और सैलरी स्लिप जैसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। ध्यान रखें कि आपके खाते में अचानक से बड़ी रकम जमा होना संदेह पैदा कर सकता है।

रिटर्न प्लान और होटल बुकिंग

वीजा अधिकारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या यह व्यक्ति वापस आएगा? इसे साबित करने के लिए आपको एक कन्फर्म रिटर्न टिकट और ठहरने की जगह का प्रमाण देना होता है। इसके अलावा, अगर आप भारत में नौकरी करते हैं या आपका अपना बिजनेस है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या बिजनेस रजिस्ट्रेशन के कागजात जरूर लगाएं। यह अधिकारियों को यकीन दिलाएगा कि आप अवैध तरीके से किसी दूसरे में रहने का प्लान नहीं बना रहे।

डॉक्यूमेंट्स: अधूरे दस्तावेज वीजा रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण हैं। चेकलिस्ट के अनुसार हर कागज को सीरिज में लगाएं। अगर आपके कुछ जरूरी दस्तावेज हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा में हैं, तो उनका अंग्रेजी अनुवाद जरूर करवाएं। साथ ही, फोटो का साइज एंबेसी की गाइडलाइंस के अनुसार ही होना चाहिए, जैसे कुछ देशों को सफेद बैकग्राउंड चाहिए होता है तो कुछ को मैट फिनिश।

इंटरव्यू के लिए रहें तैयार

यूएसए जैसे देशों के लिए आपको इंटरव्यू देना होता है। वहां घबराने की जरूरत नहीं है; बस अपने एप्लिकेशन में दी गई जानकारी पर कायम रहें और आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। झूठ बोलना या जानकारी छिपाना आपके लिए हमेशा के लिए उस देश के दरवाजे बंद कर सकता है।

उसलापुर गुड्स शेड में काम शुरू होने की आहट

बाहरी हस्तक्षेप के डर से स्थानीय ट्रक मालिकों व श्रमिकों में आक्रोश

सुनील चिंचोलकर

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। उसलापुर रेलवे गुड्स शेड में लंबे समय बाद कार्य प्रारंभ होने की संभावनाओं ने जहां स्थानीय ट्रक मालिकों और श्रमिकों में उम्मीद जगाई है, वहीं बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप और संभावित 'सिंडिकेट कब्जे' की आशंका ने चिंता और आक्रोश भी पैदा कर दिया है।

15 वर्षों बाद रोजगार बहाली की उम्मीद; 'सिंडिकेट कब्जे' की आशंका पर संघ ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की

'उसलापुर गुड्स शेड वेलफेयर ट्रक ओनर एसोसिएशन' ने कार्य शुरू होने की खबर का स्वागत करते हुए स्पष्ट किया है कि स्थानीय लोगों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघ के अनुसार, करीब 15 वर्षों से बंद पड़े इस गुड्स शेड में पहले सीमेंट, चावल और अन्य खाद्य सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य नियमित रूप से होता था। कार्य बंद होने से सैकड़ों मजदूरों और ट्रक मालिकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था। संघ ने आशंका जताई है कि तारबाहर गुड्स शेड से जुड़े कुछ प्रभावशाली ट्रांसपोर्टर उसलापुर साइडिंग पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक मिलीभगत की भी संभावना जताई गई है, जिससे स्थानीय श्रमिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर उसलापुर गुड्स शेड में संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले समय की रणनीति और संभावित चुनौतियों पर चर्चा की गई। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से रोजगार चाहते हैं, लेकिन यदि बाहरी हस्तक्षेप से विवाद की स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस संबंध में संघ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और रेलवे प्रशासन को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। बैठक में ईश्वर सिंह चंदेल, गुरमीत सिंह राणा, राशिद अली, जीत सिंह, लेबर अध्यक्ष राजेश टंडन, बलजीत सिंह डोम्मीर, महावीर सिंह संधू, हरजिंदर सिंह फौजी, इम्तियाज अली, इस्माइल भाई, शाहनवाज, संजू सिंह (MIC सदस्य), मुन्ना सिंह, मनजीत सिंह, विनोद पांडे, अस्सलाम, मुमताज खान सहित लगभग 200 ट्रक मालिक उपस्थित रहे।

उन्नाव की बेटी चारु चौहान ने सीबीएसई हाईस्कूल में 99% अंक हासिल कर बढ़ाया मान

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। उन्नाव के विकास खंड मियागंज अंतर्गत कोररी गांव की मूल निवासी और वर्तमान में सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले बेसिक शिक्षक संघ के नेता संजय सिंह चौहान की पुत्री चारु चौहान ने सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता हासिल की है। चारु दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर, कानपुर की छात्रा हैं। उनकी इस शानदार उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उल्लेखनीय है कि चारु की माता भी शिक्षिका हैं, जिससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर मार्गदर्शन मिला। चारु चौहान की इस सफलता पर शिक्षक नेताओं और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

भाजपा कर रही अत्याचार, जनता सतर्क रहे: ममता

संवाददाता

कूचबिहार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूचबिहार जिले के माथाभांगा विधानसभा क्षेत्र के घोजाडांगा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यह सभा तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार साबलू बर्मन के समर्थन में आयोजित की गई थी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न विपक्षी नेता, जिनमें उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और तेजस्वी यादव शामिल हैं, उनसे संपर्क में हैं और सभी का मानना है कि बंगाल में भाजपा अत्याचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं हैं और वह एजेंसियों के जरिए फॉर्म भरवाकर लोगों को बैठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में पैसे के दम पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना था कि इसे परिसीमन के साथ जोड़ना एक साजिश है, जिसके जरिए राज्य का विभाजन, मतदाताओं के नाम हटाने और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बिना नाम लिए केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग लोगों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, उन्हें ही डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने 'मातृशक्ति कार्ड' को लेकर भी भाजपा की आलोचना की और लोगों से अपील की कि वे किसी भी फॉर्म में अपनी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर और बैंक विवरण साझा न करें। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भले ही अभी उनके पास इसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन भविष्य में यह उनके ही नियंत्रण में होगी। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आते ही कूचबिहार में अशांति क्यों बढ़ जाती है।

जीनियस पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन

भूपेंद्र सिंह

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। कस्बा गंजमुरादाबाद स्थित जीनियस पब्लिक स्कूल में मिशन नारी शक्ति अभियान के तहत बांगरमऊ पुलिस ने बालिकाओं को जागरूक करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सुरक्षा, अधिकार और हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन नारी शक्ति अभियान के पांचवें चरण के अंतर्गत बांगरमऊ पुलिस ने जीनियस पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने विद्यालय की बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और आत्मरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।पुलिस ने छात्राओं को किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में न घबराने और तुरंत सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112 सहित अन्य महत्वपूर्ण नंबरों के बारे में जानकारी देते हुए उनके उपयोग के तरीके भी समझाए गए। साथ ही बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने, आत्मविश्वास बढ़ाने और समाज में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक जुल्फिकार अली ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से छात्राओं में जागरूकता बढ़ती है और वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती हैं। प्रधानाचार्य आदर्श पांडे ने भी बालिकाओं से इस सीख को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय की सभी बालिकाएं, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यालय प्रशासन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

त्रिपुराः पोलिंग स्टेशन पर हिंसा मामले में भाजपा विधायक समेत 35 पर एफआईआर

संवाददाता

सोनमुरा (त्रिपुरा)। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएडीसी) चुनाव के लिए वोटिंग के दिन सिपाहीजला जिले के बॉक्सनगर में एक पोलिंग स्टेशन के आसपास हुई हिंसा मामले में भाजपा विधायक तफ़ज्जल हुसैन और कुल 35 लोगों के खिलाफ कलमचौरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

यह शिकायत टिपरा मोथा दल के सदस्य अभिराम देबबर्मा ने दर्ज कराई है। उनका अभी बिश्रामगंज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि घटना वाले दिन विधायक तफ़ज्जल हुसैन अचानक करीब 200 समर्थकों के साथ पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए। इस वजह से वहां तनाव चरम पर पहुंच गया और हालात तेजी से बिगड़ गए। प्राथमिकी में बताया गया है कि उस समय पोलिंग स्टेशन के आसपास बम फेंका गया था। टिपरा मोथा सदस्य ने आरोप लगाया है कि यह हमला मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के इरादे से प्लान के साथ किया गया था। आरोप है कि जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया तो आरोपित वहां से भाग गए। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद इलाके में और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं। हालांकि, इस घटना पर राजनीतिक हलकों में कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपितों की पहचान करके कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में कोबरा जवान घायल

संवाददाता

पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटानागरा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में गुरुवार सुबह सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) में विस्फोट में हो गया। इस धमाके में कोबरा बटालियन-210 के जवान अभिनव कुमार मित्तल गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, नक्सली इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार आईईडी प्लांट कर रहे हैं और जंगल का फायदा उठाकर छिपकर हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद सुरक्षाबल पूरी सतर्कता के साथ अभियान चला रहे हैं और इलाके को नक्सल मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। घायल जवान को प्राथमिक उपचार देने के बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची भेजा गया है। छोटानागरा थाना क्षेत्र के बालिबा और आसपास के इलाकों में बीते बुधवार से ही सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों को क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद कोबरा, झारखंड पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बुधवार को भी मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने आईईडी और गोलीबारी के जरिए जवानों को निशाना बनाया था।

धर्म के आधार पर आरक्षण की बात असंवैधानिक: गृहमंत्री अमित शाह

संवाददाता

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को सरकार की ओर से परिसीमन और उसके बाद महिला आरक्षण लागू कराने से जुड़े तीनों विधेयकों को पेश किया गया। विपक्ष विधेयकों को लाए जाने का ही विरोध करता रहा। गृहमंत्री शाह ने कहा कि विपक्ष इनपर चर्चा होने दे और सरकार हर आपत्ति का जवाब देगी।

साथ ही मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा आने पर शाह ने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष ने सरकार की ओर से परिसीमन और उसके बाद महिला आरक्षण लागू कराने से जुड़े तीनों विधेयकों को विचार हेतु प्रस्तुत किए जाने का कड़ा विरोध कर दिया और इसपर बकायदा मतविभाजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष सहित केन्द्रीय गृहमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज किया। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने बार-बार कहा कि विधेयकों को पेश किए जाने का सदस्य, संविधान और सदन की विधायी क्षमता के आधार पर विरोध कर सकते हैं। कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक सहित विपक्षी पार्टियों ने विधेयकों पर अपनी आपत्ति जाहिर की। उनका कहना था कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में असल में परिसीमन विधेयक लाई है। असम व जम्मू-कश्मीर की तरह इनके माध्यम से सरकार संविधानिक संरक्षण को समाप्त कर मनमाने ढंग से परिसीमन करना चाहती है। विधेयक को विचार हेतु लाने का विरोध करने पर गृहमंत्री अमित शाह को बार-बार उठना पड़ा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार विधेयकों को जल्दबाजी में लाई है और सरकार नवीनतम जनगणना आंकड़ों से बचना चाहती है। इसमें सरकार को जातिगत जनसंख्या बतानी होगी और विपक्ष आरक्षण मांगेगा। अमित शाह ने अखिलेश के बयान को चिंताजनक बताया और कहा कि जनगणना जारी है। जातिगत जनगणना कराने का भी फैसला सरकार ले चुकी है।

मण्डलायुक्त झांसी की अभिनव पहल: बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग और मासिक मूल्यांकन कार्यों की प्रशंसा

देवेश प्रताप सिंह राठौर

झांसी, उत्तर प्रदेश। झांसी में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्टेट रिव्यू मिशन की महत्वपूर्ण बैठक कमिश्नरी सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने की, जबकि सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. पिंकी जोवल और मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में झांसी एवं चित्रकूटधाम मंडल की स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए नए मंडलीय चिकित्सालय के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तावित अस्पताल में 100 बेड का कैंसर विंग स्थापित करने पर भी विचार-विमर्श हुआ। मंडलायुक्त ने अस्पताल निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर एमबीबीएस चिकित्सकों की तैनाती तत्काल सुनिश्चित करने और वेटिंग लिस्ट तैयार रखने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। उन्होंने झांसी मंडल में स्वास्थ्य सेवाओं के मासिक मूल्यांकन की अभिनव पहल की सराहना करते हुए इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कही। साथ ही बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग और उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। सचिव डॉ. पिंकी जोवल ने स्पष्ट किया कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के समय पर संचालन, निजी नर्सिंग होम के नियमानुसार नवीनीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान को प्राथमिकता देने, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आरोग्य मेलों के प्रभावी आयोजन और स्वास्थ्य कर्मियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी, मंडल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमएस और स्टेट टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

मालिक, प्रकाशक व मुद्रक- सुनील कुमार तिवारी द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट नं. ०४, ग्राउंड फ्लोर, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नियर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं ०२, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-४०००६३ से मुद्रित व ६१७, बिल्डिंग नं. १४ नियर शिव शक्ति बिल्डिंग, गोलीबार रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुंबई-४०००५५ से प्रकाशित। **संपादक सुनील कुमार तिवारी,** RNI. NO. MAHMUL/2017/74054, **संपादकीय कार्यालय: कंटेश्वर सिंह चाल, अपोजीट एकताड़ मंडल, साईं बाबा रोड, खार (पूर्व), मुंबई- 400051, Mob. 8898271111**